www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

2 राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के...

3 नगरीय क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना...

4 इमेज को लेकर सजग थी, इसीलिए ठुकराए कई...

वर्ष: 10 | अंक: 119 | दिल्ली, शनिवार, 21 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस राज के हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर भेजेंगे वापस-अमित शाह

असम (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर सीमा सुरक्षा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में खुली सीमाओं के कारण असम में घुसपैठ हुई। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। असम के कछार जिले में एक जनसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस राज्य में सार्थक विकास पहल शुरू करने में विफल रही, वहीं असम में अब बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है, जहां प्रतिदिन लगभग 14 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है-जो देश में सबसे अधिक दरों में से एक है।

शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को अदालत से मिली राहत

मुंबई (एजेन्सी)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने कथित 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन 'पोंजी' घोटाले के मामले में जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच में शामिल 18 आरोपियों में से एक कुंद्रा पिछले महीने दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दे दी और निर्देश दिया कि विदेश यात्रा से पहले उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। अदालत कक्ष के बाहर संक्षिप्त बातचीत में कुंद्रा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मुझे घर पर बोलने नहीं देती और मेरे वकील मुझे अदालत में बोलने नहीं देते।

डीपफेक और भ्रामक सूचना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है: लोकसभा अध्यक्ष

भारत की डिजिटल अवसंरचना विश्व के लिए एक आदर्श: बिरला

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष ने डीपफेक और भ्रामक सूचना से उत्पन्न हो रही चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्हें लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग सत्य और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि तथ्यों को विकृत या दबाने के लिए। उन्होंने लोकतांत्रिक विमर्श को भ्रम और दुष्प्रचार से सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सुदृढ़ सुरक्षा उपाय विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत 'एआई फॉर डेमोक्रेसी' पर विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि एआई में लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का मार्गदर्शक सिद्धांत सदैव 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' रहा है और भारत अपने शाश्वत सभ्यतागत मूल्यों के अंतर्गत वैश्विक कल्याण की भावना के साथ कार्य करता है।

विधायी कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि एआई लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि डिजिटल संसद जैसी पहलें नागरिकों और संसद के बीच संवाद को सरल बना रही हैं तथा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में डिजिटल और सूचना डिवाइड को पाट रही हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल संसद पहल के अंतर्गत संसदीय कार्यवाही को कागजरहित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। एआई उपकरणों की सहायता से हजारों घंटों की संसदीय बहसों और अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से संकलित कर आसानी से खोजने योग्य और सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों की निकटता से निगरानी कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही सुदृढ़ होती है।

भारत की भाषाई विविधता का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने संसद भाषिणी पहल के महत्व को रेखांकित किया, जिसके माध्यम से एआई आधारित अनुवाद उपकरणों की सहायता से संसदीय बहसों को अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देशभर के नागरिक अपनी भाषा में संसदीय चर्चाओं को समझ और उनसे जुड़ सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और सहभागिता मजबूत होती है।

लोक सभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंचों पर, विशेषकर पीठासीन अधिकारियों की वैश्विक सहभागिताओं के दौरान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने के महत्व पर बल दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि विधायी दक्षता के लिए एआई के उपयोग में भारत के नवाचारों की विश्व स्तर पर सराहना की जा रही है। आधुनिक डेटा प्रणालियां सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बेहतर समझने में सहायता कर रही हैं, जिससे अधिक जन -केंद्रित नीति निर्माण संभव हो रहा है।

श्री बिरला ने कहा कि भारत की एआई रणनीति समावेशी विकास के सिद्धांत पर आधारित है; और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को तीव्र करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाकर, स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ कर तथा किसानों को डेटा-आधारित समाधान उपलब्ध कराकर एआई लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, विशेषकर वंचित और असंगठित क्षेत्रों में।

अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस का भव्य आयोजन

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को उगते सूरज की भूमि 'अरुणाचल प्रदेश' और 'नीले पहाड़ों के प्रदेश' मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं दिल्ली सरकार के सभी माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने दोनों राज्यों के नागरिकों एवं सभी देशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23 वें और अरुणाचल प्रदेश को 24 वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' संकल्प की दिशा में हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता के सशक्त प्रतीक हैं। पूर्वोत्तर के राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध परंपराओं और देशभक्ति की भावना से पूरे राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। मिजोरम की हरियाली और उच्च साक्षरता दर प्रेरणा हैं एवं अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध मठ, सुंदर घाटियाँ एवं जनजातीय विविधता अंतरराष्ट्रीय आकर्षण हैं। कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाने के संकल्प की कड़ी में आज एक और सुनहरा दिन है। स्थापना दिवस जैसे अवसर देश की विविध संस्कृति को समझने और उसे सम्मान देने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने दोनों राज्यों की प्रगति, शांति और समृद्धि की कामना की।

दिल्ली देश का दिल
-कपिल मिश्रा

कार्यक्रम में दोनों प्रदेशों से आए 16 कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। फोक फ्यूजन एवं चैलम नृत्य के दौरान रंग-बिरंगे परिधानों से सजे कलाकारों और पारंपरिक संगीत की धुनों ने दिल्ली सचिवालय परिसर को पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक छटा से सराबोर कर दिया।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं अन्य दर्शकों ने दोनों राज्यों के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले कलाकारों का उत्साह वर्धन किया।

2025 में 156 करोड़ पर्यटकों के साथ यूपी बना देश का अग्रणी पर्यटन केंद्र: मुख्यमंत्री योगी

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में लगभग 156 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जो प्रदेश की बदलती छवि और सुदृढ़ आधारभूत संरचना का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

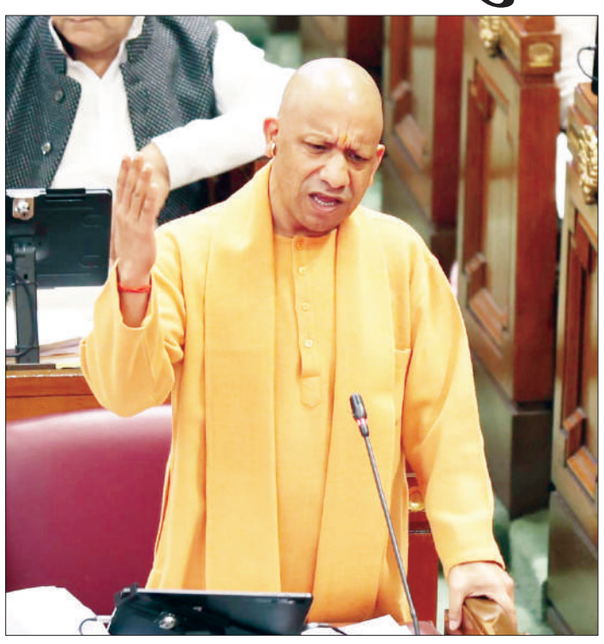

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, विंध्य कॉरिडोर, चित्रकूट और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख आस्था स्थलों का व्यापक विकास किया गया है। इन स्थलों पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सामाजिक समरसता और महापुरुषों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं एवं पार्कों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह कदम सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि यूनेस्को ने लखनऊ को 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह सम्मान प्रदेश की समृद्ध पाक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाला है। उन्होंने बताया कि आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम परिवर्तित कर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्मारक एवं संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय नायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हस्तिनापुर, सारनाथ, श्रावस्ती और बटेश्वर को आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित कर पर्यटन की नई संभावनाएं सृजित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बागपत के पुरा महादेव में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र को पीपीपी मोड पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए टाटा संस के साथ एमओयू किया गया है। यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से होमस्टे स्थापना हेतु 2 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आस्था, संस्कृति, विरासत और आधुनिक विकास के संतुलन के साथ पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और यह उपलब्धि प्रदेश के नागरिकों के सहयोग और सरकार की स्पष्ट नीति का परिणाम है।

14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे मोदी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। असम में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बराक घाटी के विकास के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को सिलचर में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे और राज्य के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और 22,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। शर्मा ने सिलचर में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से गुवाहाटी और सिलचर के बीच का सफर मौजूदा आठ घंटे से घटकर साढ़े चार घंटे का रह जाएगा। शर्मा ने बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है और सड़क निर्माण जल्द ही शुरू होगा। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सिलचर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिलचर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बृहस्पतिवार को इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी...समय कम बचा है लेकिन हम मार्च तक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे।

श्री श्याम महिला शक्ति फाउंडेशन द्वारा फाल्गुन महोत्सव के तहत भजन संध्या आयोजित

संजना भारती संवाददाता

श्रीगंगानगर। श्री श्याम महिला शक्ति फाउंडेशन द्वारा सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर के समीप मनन विहार स्थित कार्यालय में फाल्गुन महोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी सुशील अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता गजरा तथा संस्थापक सोहनलाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री श्याम सलोना मस्त मंडल, श्रीगंगानगर के विख्यात कलाकारों ने श्री श्याम बाबा के चरणों में भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों द्वारा सभी श्याम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

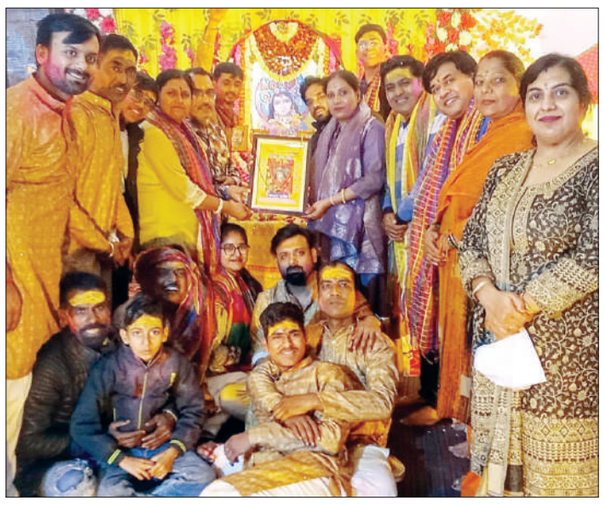

इस मौके पर श्याम बाबा का अत्यंत मनमोहक तथा अलौकिक श्रृंगार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव में फूलों व गुलाल की होली खेली गई तथा इत्र वर्षा व चंग की थाप पर हुए धमाल ने माहौल को पूरी तरह श्याम रंग में सराबोर कर दिया। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए श्री श्याम सलोना मस्त मंडल द्वारा श्री श्याम महिला शक्ति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता गजरा तथा संस्थापक सोहनलाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता गजरा ने सफल आयोजन के लिए समस्त सहयोगकर्ताओं, पदाधिकारियों, सदस्यों व श्याम भक्तों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर श्री श्याम महिला शक्ति फाउंडेशन व श्री श्याम सलोना मस्त मंडल के सदस्य एवं श्याम भक्त उपस्थित थे।

बलजिंदर सिंह चौंदा ने पंजाब एस.सी. भूमि विकास और वित्त निगम के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब अनुसूचित जातियां और भूमि विकास और वित्त निगम के नव-नियुक्त चेयरमैन बलजिंदर सिंह चौंदा ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की मौजूदगी में सरकारी तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रियों ने नव-नियुक्त चेयरमैन को बधाई दी।

इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एस.सी. वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, आसान ऋण सुविधाएं और ऋण माफी जैसे ऐतिहासिक फैसले यह साबित करते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर योग्य लाभार्थी तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। उन्होंने आगे कहा कि नव-नियुक्त चेयरमैन के नेतृत्व में निगम एस.सी. वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाएगा।

कार्यभार संभालने के बाद चेयरमैन श्री बलजिंदर सिंह चौंदा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया। चेयरमैन ने कहा कि अनुसूचित जातियों के वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर ठोस और परिणाम-केंद्रित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एस.सी. वर्ग से संबंधित पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरल, पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

सांसद ने यातायात की समस्या को रेल मंत्री के सामने उठाया

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं/गुन्नौर। लोकसभा क्षेत्र बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने बबराला-अनूपशहर मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 58/बी पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण यातायात जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विस्तृत पत्र लिखकर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की है।

आदित्य यादव सांसद ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के अंतर्गत आने वाला बबराला-अनूपशहर मार्ग क्षेत्र का प्रमुख एवं अत्यधिक व्यस्त संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में आम नागरिक, विद्यार्थी, किसान, व्यापारी और मरीज प्रतिदिन आवागमन करते हैं। मार्ग के दोनों ओर स्थित अनेक ग्रामों की रोजमर्रा की गतिविधियाँ-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार-इसी मार्ग पर निर्भर हैं। इस रेलवे फाटक संख्या 58/बी से प्रतिदिन लगभग 25 से 30 सवारी गाड़ियाँ एवं मालगाड़ियाँ गुजरती हैं।

ट्रेनों के आवागमन के दौरान फाटक लंबे समय तक बंद रहने से दोनों ओर कई-कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे यात्रियों को समय की भारी हानि, ईंधन की बर्बादी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहनों को भी जाम में फंसना पड़ता है, जिससे आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित होती हैं। सांसद ने अपने पत्र में यह भी रेखांकित किया कि अलीगढ़-बरेली के मध्य डबल लाइन रेलवे परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पूर्ण होने के उपरांत इस रेल खंड पर ट्रेनों की संख्या में संभावित वृद्धि से फाटक पर जाम की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए ROB का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

सांसद आदित्य यादव ने रेल मंत्री से जनहित को प्राथमिकता देते हुए रेलवे फाटक संख्या 58/बी पर ROB निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज बनने से क्षेत्र में निर्बाध, सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा गुन्नौर विधानसभा सहित आसपास के अनेक ग्रामों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

रक्तदान के जरिए अनेको लोगों का जान बचा चुके हैं जलपुत्र अजय राय

संजना भारती संवाददाता

पटना। 'रक्त दान जीवन दान' के वाक्यां को चरितार्थ करने रहें दक्षिण टोला डुमरेजनी रोड के रहने वाले युवा अजय राय जिसका ताजा उदाहरण यह है की डुमरांव नगर के वार्ड-25 के अरुण कुमार श्रीवास्तव को AB+ ब्लड की सख्त जरूरत थी जिसकी जानकारी वार्ड 20 के पार्षद टिंकू सिन्हा ने अजय राय को दिया।

वही सूचना पाते ही अजय ने रक्तदान कर पीड़ित अरुण कुमार श्रीवास्तव के जान बचा एक नई जिंदगी दिया। रक्तादन के इस नेक कार्य को स्थानीय लोगों एवं पीड़ित परिवार ने अजय के इस नेक कार्यों की जमकर सराहना किया। विदित हो की कोरोना काल में भी अजय ने अनेको लोगों को ब्लड उपलब्ध करा जान बचाया था। जिसके लिए डीएम ने अजय को सम्मानित भी किया था। अजय युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हैं। युवा उन्हें अपना प्रेरणास्रोत भी मानते हैं।

सम्पादकीय

ट्रिपल इंजन से बदलेगी राजधानी की तस्वीर!

वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श महानगर के रूप में विकसित करना चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन किया जाए और देखा जाए कि तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ दिल्लीवासियों को कितना और कैसे मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और आगामी संकल्पों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल नई योजनाओं की शुरूआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की लंबित और अधूरी परियोजनाओं को भी गति दी है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की पहल, तथा महिलाओं और छात्रों के लिए नई राहतकारी योजनाओं का खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के कारण विकास कार्यों में समन्वय और गति दोनों आई है। ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप में सामने आया है। दिल्ली सरकार को अब पूंजीगत व्यय के लिए ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित किए जाने से आधारभूत ढांचे के विकास में धनाभाव की आशंका कम हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा पीएम भीम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की समयावधि बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को सफलता मिली है। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ अब राजधानी के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बीच नई सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का दावा किया गया है। पिछले वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और परिणामों पर सवाल भी उठे। नई सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करे। परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी गति लाने का प्रयास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़कों के सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की जीवनरेखा रही है, अब किराए में राहत या छात्रों के लिए विशेष प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं तो इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है। एक वर्ष में कुछ परियोजनाओं को गति मिली है, किंतु राजधानी जैसे विशाल महानगर में ठोस परिणामों के लिए निरंतर प्रयास अपेक्षित हैं। सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और वायु प्रदूषण की है। बीते दशक में दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाने लगी। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का संकट है। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं का उल्लेख किया है-जैसे हरित आवरण बढ़ाना, निर्माण कार्यों पर निगरानी, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। परंतु यह भी सत्य है कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं, इसके लिए कठोर क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सहयोग और जनसहभागिता की आवश्यकता होगी। यमुना की सफाई भी दिल्ली की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के नाम पर योजनाएं बनती रहीं, बजट खर्च होता रहा, पर परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। वर्तमान सरकार ने यमुना को स्वच्छ और पर्यटन योग्य बनाने का संकल्प दोहराया है। यदि सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण और नदी तट के पुनर्विकास की योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो यह दिल्ली की छवि को नया आयाम दे सकती हैं। यमुना का पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी अवसर है। महिलाओं और बेटियों के लिए घोषित योजनाएं-जैसे लखपति बिटिया योजना-सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं।

जयंती

शान्ति स्वरूप भटनागर

जन्म: 21 फरवरी, 1894, शाहपुर, पाकिस्तान, मृत्यु: 1 जनवरी, 1955, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, जो औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के निदेशक रहे। इन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में अमूल्य योगदान दिया।

पुण्यतिथि

ओम प्रकाश

जन्म: 19 दिसंबर, 1919 जम्मू, मृत्यु: 21 फरवरी, 1998 मुम्बई, भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। ओमप्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'पड़ोसन', 'जूली', 'दस लाख', 'चुपके-चुपके', 'बैराग', 'शराबी', 'नमक हलाल', 'प्यार किए जा', 'खानदान', 'चौकीदार', 'लावारिस', 'आंधी', 'लोफर', 'जंजीर' आदि शामिल हैं। उनकी अंतिम फिल्म 'नौकर बीवी का' थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फि ल्मों में वे खासे सराहे गए। 'नमक हलाल' का दद्दू और 'शराबी' का मुंशीलाल बनकर ओमप्रकाश ने प्रत्येक भारतीय के दिल में जगह बनाई।

कल मिलेंगे

सास-बहू, पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है। उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना।
वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी?
बहू-कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं।

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। **मुद्रक**-देवानंद राय।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत सियासी मायने

-कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

> महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है

चिरंजीवी सदन 'राज्यसभा' के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटें के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।

जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहां तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उत्तरप्रदेश की 10 और झारखंड, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना आदि की 20 से अधिक सीटों के लिए नवम्बर में चुनाव होंगे।

जहां तक उच्च सदन राज्यसभा में वर्तमान दलगत स्थिति की बात है तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जहां भाजपा के 103 और एनडीए के 121-129 सांसद हैं। जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 78-80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 27 सांसद हैं। जहां तक इन चुनावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो इन चुनावों में एनडीए को 7-9 या इससे अधिक सीटों का लाभ मिलने का अनुमान है, जिससे उनकी संख्या 145 तक पहुंच सकती है। जबकि विपक्ष को 5 सीटें खोने का खतरा, खासकर बिहार, महाराष्ट्र में है। इससे भाजपा को राज्यसभा में अब कोई भी विधेयक पास करना आसान होगा और सुपरमेजॉरिटी की ओर बढ़त भी उसे मिलेगी।

सवाल है कि इन चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की संभावना है तो राजनीतिक विश्लेषकों को अनुमान है कि एनडीए को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 48 या इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनकी ताकत 129 से बढ़कर 140+ हो सकती है। पहले चरण के 37 सीटों पर 5-7 का लाभ अनुमानित है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बाद के चरणों से भी उसे अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 71-75 खाली सीटों में से एनडीए को नेट 7-9 या 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान में एनडीए के 121-129 सदस्य हैं, इसलिए चुनाव बाद 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बाद के जून-नवम्बर वाले दूसरे चरणों के प्रभाव की बात है तो वे भी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में भाजपा को 7-8 मिलनी संभावित है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना आदि में स्थिरतामिलेगी।, कुल मिलाकर सुपरमेजॉरिटी (123+) पक्की होगी। जबकि विपक्ष को 5 नुकसान होगा। जहां तक इन चुनावों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की बात हैं तो इंडिया गठबंधन को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 71-75 सीटों में से नेट 5 का नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी संख्या 80 से घटकर 75 रह जाएगी। पहले चरण के 37 सीटों पर भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है, हालांकि कुछ राज्यों में स्थिरता संभव है। विश्लेषकों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक वर्तमान 80 सीटों से 75 पर सिमट सकता है। कांग्रेस को विशेष रूप से 8 सीटें खोने का खतरा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह की सीटें भी शामिल हैं।

वहीं बाद के चरणों का प्रभाव भी उसपर पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें में से सपा को 2-3 मिलनी संभावित हैं, लेकिन कुल नुकसान होगा। जबकि कर्नाटक, झारखंड में 1-1 सीटों का नुकसान संभव है। ओवरऑल, एनडीए के लाभ से इंडिया कमजोर होगा।

जहां तक राज्यवार स्थिति की बात है तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और एक सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और एनडीए के खाते में 4 सीटें सुनिश्चित हैं, जबकि 5 के लिए जोर आजमाइश बढ़ेगी। क्योंकि यहां 35 सीटों के साथ I.N.D.I.A. एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में 5 विधायकों वाले AIMIM की भूमिका अहम हो जाती है। यदि पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो बिहार में विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हो जाते हैं और विपक्ष एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व और विपक्षी एकता की के लिए अग्निपरीक्षा होगा।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे, जहां अभी 2 सीट बीजेपी और 2 बीजेडी के पास है लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और यहां भी बीजेपी जीत दर्ज करने की स्थिति में है।

रही बात तेलंगाना की तो वहां से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी रिटायर हो रहे हैं और बीआरएस के एक कैंडिडेट का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस दोनों सीटें जीत सकती है और हिमाचल में भी कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम से तीन पश्चिम बंगाल से 5 और तमिलनाडु से भी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चूंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के पास राज्यसभा में अपना संख्याबल कायम रखने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग से निपटने की चुनौती विपक्ष के सामने रहेगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने अपने विधायको को एकजुट रखने की चुनौती हमेशा होती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। इसलिए आने वाले राज्यसभा चुनावों को देखें तो चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यहां पर कांग्रेस और सहयोगी दलों को फूंक-फूंक करकदम रखना होगा। हालांकि कुछ सीटों पर तो रिजल्ट पहले से ही तय है, लेकिन अगर विपक्ष क्रॉस वोटिंग को रोक पाता है तो उसके हाथ भी कुछ सीट आ सकतीहैं। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष 75 सीटों पर होने वाले चुनावों में विपक्ष यदि कारगर रणनीति नहीं बनाता है तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संख्या और घट सकती है, इतना तय है।

जहां तक इन चुनावों में प्रमुख नेताओं के प्रभावित होने की बात है तो कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जदयू नेता हरिवंश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (6 मंत्री सहित) शामिल हैं। वहीं बीएसपी राज्यसभा से साफ हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं राजद और बीजद समेत कई दलों की सीटें घटेगी।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तारः एक सार्थक पुकार

-ललित गर्ग

> सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है। समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं। रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है। लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है।

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके।

2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार

भारत ने बांग्लादेश पर ले डाला तगड़ा फैसला..तारिक भी हैरान!

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होते ही धीरे-धीरे हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम बनते ही तारिक रहमान भारत को लेकर जिस तरह की दिलचस्पी दिखा रहे हैं और भारत भी जिस तरह की पहल कर रहा है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती की ओर सकारात्मक कदम है। बांग्लादेश की कमान संभालते ही तारिक रहमान ने जो भी बयान दिए हैं या फैसले लिए हैं, वह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पिछले 18 महीने से दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ था, अब वह जल्द खत्म होने वाला है। और फिर से विकास और शांति के रास्ते खुलने वाले हैं। जहां तारिक रहमान ने हिंदुओं को लेकर कट्टरपंथियों की जमात को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साथ ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में विकास वाली नीति के साथ सरकार चलाने के एजेंडे को सबके सामने रख दिया है। यही नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मोहम्मद यूनुस के उन फैसलों को भी बदलना शुरू कर दिया है जिनको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा भारत विरोधी अफसरों पर भी एक्शन तेज कर दिया। सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। नफरती गैंग के खिलाफ तारिक रहमान के इस सख्त रुख को देखकर भारत ने भी बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। इसके लिए भारत ने बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाते हुए संकेत दिया है कि वह जल्द ही बांग्लादेश में अपनी पूरी वीजा सेवाएं बहाल करने जा रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई शुरूआत के तौर पर देखा जा रहा है।

बीवी को पीटना गैरकानूनी नहीं! बस हड्डी नहीं टूटनी चाहिए!

(एजेन्सी)।

पाकिस्तान की हर बेगम इन दिनों खौफ में है। डर सिर्फ तालिबान का नहीं बल्कि खौफ नए तालिबानी कानून का है। सुनने में आपको यह कोई पुरानी खबर लग रही होगी कि अफगानिस्तान में तालीबानियों के राज में यह भला कौन सी नई बात है। पहले भी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें महिलाओं को सरेआम कोड़े मारने, पत्थर से मारने और यहां तक कि सिर कलम करने जैसी घटनाएं खुलेआम होती हैं। ऐसी सजाओं से भला कौन खौफ नहीं खाएगा। लेकिन अफगानी बेगमों का यह खौफ ऐसी सख्त अमानवीय सजाओं तक सीमित नहीं बल्कि डर है हर रोज पीटे जाने का। अफगानिस्तान में काला कानून बीवी को पीटना गैरकानूनी नहीं। 90 पेज का तालीबानी फरमान बीवियों को पीटो बस जख्म ना दिखे। यानी तालीबानियों का अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क हो गया है जहां एक छोटी सी शर्त पूरी कर ली तो औरतों को पीटना कानूनी अपराध नहीं।

इस नए फरमान ने घरेलू हिंसा को एक अलग तरह से लीगल कर दिया है। अब इस देश में मर्दों को खुलेआम अपनी बीवियों पर हाथ उठाने की इजाजत मिल गई है। बस एक छोटी सी शर्त रखी गई है। तालीबान के नए कानून के मुताबिक एक पति अपनी पत्नी और बच्चों को शारीरिक सजा दे सकता है। इसमें चौंकाने वाली शर्त यह है कि मारपीट तब तक कानूनी है जब तक कि उससे हड्डी ना टूटे या कोई खुला घाव ना हो। अगर पति बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है और महिला की हड्डी टूट जाती है तब जाकर पति को अधिकतम 15 दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए भी पत्नी को अदालत में अपनी चोट साबित करनी होगी। अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति की इजाजत के बिना अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है।

जोनाथन ट्रॉट का अफगानिस्तान संग चार साल का भावनात्मक सफर समाप्त

(एजेन्सी)।

साल 2022 में बेलफास्ट में जब जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभाला, तब परिस्थितियां आसान नहीं थीं। मौजूद जानकारी के अनुसार वह अपनी यात्रा का खर्च स्वयं वहन कर आयरलैंड पहुंचे थे और शुरूआती दिनों में उनके पास आधिकारिक किट तक उपलब्ध नहीं थी। उस समय शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि यह नियुक्ति अफगान क्रिकेट के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी।

बताते चलें कि ट्रॉट को यह जिम्मेदारी अप्रत्याशित रूप से मिली। यह पद पहले उनके मेंटर ग्राहम थोर्पे को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रॉट पर भरोसा जताया। उस समय टीम के पास स्वाभाविक प्रतिभा तो भरपूर थी, लेकिन पेशेवर संरचना, योजना और अनुशासन की स्पष्ट प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता थी। गौरतलब है कि ट्रॉट ने कार्यभार संभालते ही बुनियादी ढांचे और पेशेवर संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया। समय पालन, अभ्यास सत्रों की नियमितता, फिटनेस मानक और मैच पूर्व तैयारी को संस्थागत रूप दिया गया। सांस्कृतिक समन्वय भी उनके लिए महत्वपूर्ण पहलू रहा। अभ्यास कार्यक्रम और नमाज के समय के बीच संतुलन स्थापित करने जैसे विषयों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया, जिससे टीम के भीतर विश्वास और सम्मान का वातावरण बना।

अफगान खिलाड़ियों की सामाजिक पृष्ठभूमि ने भी कोचिंग प्रक्रिया को प्रभावित किया। कई खिलाड़ी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में पले-बढ़े थे। भाषा और शिक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आईं। टीम मूल्यों और रणनीतिक दस्तावेजों को सभी खिलाड़ियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए संवाद की शैली में बदलाव करना पड़ा। ट्रॉट ने तकनीकी निर्देशों के साथ-साथ व्यवहारिक और प्रेरणात्मक संवाद को अहमियत दी।

सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा उछला

(एजेन्सी)।

शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 316 अंक की बढ़त के साथ जबकि निफ्टी 25,550 के पार बंद हुआ। बैंकिंग और धातु शेयरों में खरीदारी, व्यापार समझौते में प्रगति को लेकर आशावाद के साथ पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी की खबरों से बाजार को समर्थन मिला। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 316.57 अंक यानी 0.38 प्रतिशत चढ़कर 82,814.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 633.94 अंक बढ़कर 83,132.08 अंक तक पहुंच गया था।

एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 116.90 अंक यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,571.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 209.2 अंक उछलकर 25,663.55 अंक के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशकों द्वारा शेयर की अंधाधुंध बिकवाली से बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 1,236.11 अंक और एनएसई निफ्टी 365 अंक टूट गया था।

शुक्रवार को सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावरग्रिड, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, टाइटन, मारुति सुजुकी इंडिया, एक्सिस बैंक और इंडिगो के शेयर में सबसे अधिक तेजी रही। दूसरी तरफ, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इटर्नल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदाणी पोर्ट्स के शेयर नुकसान में रहे। प्रमुख विनोद नायर ने कहा, भारतीय शेयर बाजारों ने एक दिन पहले की भारी गिरावट के बाद जोरदार वापसी की। बड़े शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। व्यापार समझौते को लेकर स्पष्ट संकेतों और पैक्स सिलिका में भारत के प्रवेश से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। नायर ने कहा कि बैंकिंग और धातु कंपनियों के शेयरों में तेजी ने भी बाजार को वापसी करने में मदद की। व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.45 प्रतिशत चढ़ा जबकि बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.07 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,265 शेयर गिरावट में रहे जबकि 1,917 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई और 167 शेयर अपरिवर्तित बंद हुए। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,89,341.06 करोड़ रुपये बढ़कर 4,67,11,355.63 करोड़ रुपये हो गया।

साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स 187.95 अंक यानी 0.22 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी में 100.15 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की तेजी रही। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच अंततः सूचकांक बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। भू-राजनीतिक चिंताओं और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निफ्टी कमजोर खुला, हालांकि चुनिंदा बड़े शेयर में खरीदारी से सत्र के आगे बढ़ने के साथ सूचकांक संभल गया और सकारात्मक दायरे में बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शोध प्रमुख (संपत्ति प्रबंधन) सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि पीएसयू बैंक शेयरों पर ध्यान बना रहा और वे 1.7 प्रतिशत चढ़े।

नगरीय क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय

हाजीपुर। जिलाधिकारी, वैशाली, वर्षा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि एवं कौशल के अनुरूप स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें।

इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा सभी नगर निकाय क्षेत्र में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की गहन जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए वार्ड स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जिनमें संबंधित कर्मी, आवास सहायक, जीविका से जुड़े प्रतिनिधि एवं अन्य सहयोगी कार्मिक शामिल हैं। सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र में जाकर आवेदनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक एवं पात्र लाभुकों तक ही पहुंचे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महिलाओं को केवल अनुदान राशि उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ना भी आवश्यक है।

इसी क्रम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिससे वे लघु उद्यम, घरेलू उद्योग, सेवा आधारित कार्य या अन्य आयवर्धक गतिविधियों को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर सकें। जिलाधिकारी द्वारा योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

हरियाणा में सामाजिक न्याय की उड़ाई जा रही धज्जियां : राजेंद्र तंवर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

भिवानी। ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा है कि हरियाणा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का हक छीनने का काम रहे हैं। उसका मिसाल पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलती जैसा हरियाणा में हो रहा है।

■ 1 मार्च को पानीपत में ओबीसी ब्रिग्रेड की प्रदेश कार्यकारिणी की होगी मीटिंगः तंवर

राजेंद्र तंवर ने कहा कि एचपीएससी द्वारा पिछड़ा वर्ग को करीब 400 बच्चों को जिन्होंने एक्जाम और इंटरव्यू पास कर लिए थे उनको बिना बात निकाल दिया गया। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष में एक बार बनवाना होता है। 1 मार्च को पानीपत में पुरानी सब्जी मंडी कश्यप धर्मशाला में एक ओबीसी ब्रिगेड की एक राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के बच्चों के साथ हो अन्याय के खिलाफ आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी।

राजेंद्र तंवर ने कहा कि जुलाई 2024 में एचपीएससी द्वारा सेकेंड क्लास की नौकरियां निकाली गई जिसमें न्यायायीक विभाग, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी व पिजीटी की वैकेंसी निकाली गई। इनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अगस्त 2024 थी। उस समय ओबीसी की क्रीमीलेयर सीमा हरियाणा में 6 लाख रुपए थी। ये वैकेंसी निकलने के बाद हरियाणा सरकार ने क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रुपये कर दी। काफी बच्चों ने ओबीसी का सर्टिफिकेट 6 लाख रुपये सीमा के तहत बनवा लिया और कुछ बच्चों ने 14 अगस्त के बाद सर्टिफिकेट बनवाए, क्योंकि एचपीएससी की साइट बंद हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि उन बच्चों को ये कहकर नौकरी ज्वाइन नहीं करवाई कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नई गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बना और कुछ को यह कहकर बाहर निकाल दिया आपका सर्टिफिकेट 14 अगस्त के बाद बना है। करीब 400 बच्चों को बिना बात के बाहर निकाल दिया गया। ये बच्चे सभी ओबीसी समाज के है, जबकि एचपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार ओबीसी का सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार बनवाना पड़ता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से है और रणबीर गंगवा भी ओबीसी समाज से है।

ओबीसी समाज के बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये लोग इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री का हमे क्या फायदा है।

गांव बिरथे बाहरी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ग्रामीणों ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर लिया भाग

गांव बीरथे बाहरी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। (छायाः एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। खंड राजौंद के गांव बिरथे बाहरी स्थित रचना आंगनबाड़ी केंद्र में सिविल सर्जन डॉ. रेनू चावला के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राजौंद डॉ. संदीप सिंह के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को बेटियों के महत्व, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समान परवरिश के प्रति जागरूक किया गया तथा अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई गई।

चंद्रकला एएनएम और सीमा एएनएम ने कहा कि बेटियां समाज की धुरी हैं और आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं की निंदा करते हुए बेटा-बेटी में भेदभाव खत्म करने का आह्वान किया। इस अवसर पर रामनिवास एमपीएचडब्ल्यू ने क्षय रोग के लक्षण, जांच, उपचार और पोषण संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी वर्कर रचना देवी, मलकी देवी, आशा वर्कर नीतू, पिंटिया सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं।

ट्रान्सपोर्ट नगर प्रकरण में डीएम पोर्टिको पर किसानों ने किया धरना-प्रदर्शन

डीएम पोर्टिको में धरना-प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता और किसान। (छायाः एसबी)

एसबी संवाददाता

वाराणसी। शुक्रवार को मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के Special Ieave Petition Appeal No 20832/2023 में 16/02/2026 को हुये अंतरिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रीट संख्या 36353/2023 में 21/11/2023 से ही किसानो के पक्ष में मिले स्थगन आदेश जो वर्तमान समय में प्रभावी है का वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा खुला उलंघन करने से आक्रोशित सैकड़ो अधिवक्ताओ एवं किसानों का हुजुम दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम तथा मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक एवं अधिवक्ता विनय शंकर राय "मुन्ना" के नेतृत्व में जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार से उनके कचहरी कार्यालय में मिलकर दोनो माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति दिया जिसपर जिलाधिकारी ने न्यायालय के आदेश का लीगल राय लेकर दो दिन में उच्च अधिकारियो संग किसानो से वार्ता करने एवं तब तक सम्पूर्ण कार्यवाई रोकने का दिया आश्वासन।

प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने कहा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत की संवैधानिक पीठ के अंतरिम आदेश एवं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा खुला उलंघन करना और मीडिया में 17 फरवरी को प्रेस रीलीज जारी कर कहना कि किसानो के पक्ष में वर्तमान समय में कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नही है यह माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा सीधा अवमानना करना है जो पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण एवं अवैधानिक कृत्य है।

■ जिलाधिकारी को किसानों ने दिया ज्ञापन

किसान नेता विनय शंकर राय "मुन्ना" ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर भ्रामक प्रेस रिलीज वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा जारी करना एवं उसके बाद प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर में व्यवसायिक भूखंड आवंटन हेतु 18 फरवरी को लाटरी प्रक्रिया अपनाना और मौके पर किसानो के जमीन और मकान पर जबरदस्ती कब्जा और उत्पीड़न की कार्रवाई तीव्र गति से करना उनके अवैधानिक कृताय एवं अहंकार का स्पष्ट प्रमाण है जिसको वाराणसी कानून के रखवाले अधिवक्ता एवं धरती के पालनहार अन्नदाता किसान बर्दाश्त नही करेगा, श्री राय ने तीन दिन में वीडीए उपाध्यक्ष पर कठोर वैधानिक कार्रवाई नही हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही तत्काल बंद नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई के ऐलान हेतु काशी के अधिवक्ता, किसान, मजदूर एवं नौजवान खुली पंचायत करेगे और निर्णायक अंदोलन का आगाज करेगे।

प्रमुख रूप से सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री आशीष सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, शैलेन्द्र राय, मनीष सिंह, अभय सिंह, दीपक राय कान्हा, विश्वनाथ कुंवर, प्रवीन उपाध्याय, अंकुर प्रकाश, रविन्द्र प्रताप सिंह यादव, श्रीमती सीता, भूपेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह सहित सैकड़ो अधिवक्ता एवं डा विजय नरायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, प्रेम शाह, अमलेश पटेल, रमेश पटेल, विजय गुप्ता, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, रमाशंकर पटेल, प्रमोद पटेल, राम नारायण पटेल, सुरेश पटेल, विकास पटेल, मदनलाल, सुभाष पटेल, सोमनाथ पटेल, बलराम पटेल, प्रेम पटेल, रवि पटेल, हनुमान पटेल, शुभम पटेल, लक्ष्मी नारायण, विजय पटेल, कल्लू पटेल, सुजीत पटेल, नीतीश पटेल, सोनू पटेल, अजीत पटेल, राजनाथ पटेल, वकील, चंदन पटेल, दीपू पटेल, रमेश पटेल, डंगरू पटेल, रघुवर पटेल, राजेंद्र पटेल नीरज पटेल, नीतीश पटेल, रामकुमार पटेल, संजू बाबा, महेंद्र पटेल, सोनू पटेल, देवनाथ पटेल, राहुल पटेल, नरेश पटेल, रतन पटेल, रोहित पटेल, बंटी, संदीप पटेल, काशीनाथ पटेल, मुन्ना पटेल, रमाशंकर पटेल, सुरेश मौर्या सहित सैकड़ो किसान शामिल थे।

हरियाणा सरकार के विभागों, अनुभागों, उपक्रमों, निगमों को केवल सरकारी बैंकों में ही खाते खोलने होंगें : एलडीएम सुमन कुमार

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। एलडीएम सुमन कुमार ने बताया कि वित्त विभाग (इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल), हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए गए हैं कि हरियाणा सरकार के सभी विभाग, अनुभाग, उपक्रम, निगम अपने सभी प्रोजेक्ट/स्कीम इत्यादि के खाते केवल सरकारी बैंकों में ही खोल सकते हैं तथा इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना खोला गया कोई भी बैंक अकाउंट इरेगुलर माना जाएगा और उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ कोई डिपार्टमेंट/ ऑर्गनाइजेशन किसी कॉपोरेंट/प्राइवेट सेक्टर बैंक में बैंक अकाउंट खोलने का प्रपोजल रखता है, वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट (इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल) से पहले से मंजूरी लेना जरूरी होगा तथा सरकारी बैंक में खाता न खोलने के खास कारण बताना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निधियों के प्लेसमेंट के मामलों में अधिक ब्याज दर सुनिश्चित करने हेतु सेविंग या करंट अकाउंट के स्थान पर फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अथवा अन्य डिपॉजिट खातों का उपयोग किया जाए।

परिवहन मेले का आयोजन

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। बदायूं परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी अवनीश राय बदायूं द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में परिवहन कार्यालय बदायूं में एक मुक्त कर योजना के तहत 7500 kg तक के वाहनों को आच्छादित करने हेतु दिनांक 20 से 21 फरवरी 2026 तक परिवहन कार्यालय बदायूं में परिवहन मेले का आयोजन किया जा रहा है आज दिनांक 20-02-2026 को परिवहन मेला के अंतर्गत कार्यालय में बूथ लगाया गया। शासन द्वारा 30 दिसंबर 2026 की अधिसूचना के अंतर्गत 7500 किलोग्राम तक वाहन क्षमता वाले वाहनों पर एक मुक्त कर व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था को सुचारू से संचालित करने हेतु ज्ञानेंद्र वरिष्ठ सहायक एवं असीम राजा प्रधान सहायक के द्वारा समस्त वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों को शासन की नीतियों से अवगत कराया गया।

उक्त अधिसूचना के पश्चात 7500 किलोग्राम वजन वाले किसी भी वाहन का त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कर की गणना नहीं होगी, समस्त वाहन इस कैटेगरी के अंतर्गत एक मुक्त कर व्यवस्था के तहत 15 वर्ष की कर धनराशि जमा करेंगे।

वाहन स्वामियों को अवगत कराया गया कि एक मुफ्त कर व्यवस्था के पश्चात ही वाहन का फिटनेस, परमिट वाहन का हस्तांतरण संभव हो सकेगा। उक्त योजना के द्वारा वाहन स्वामियों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कर को जमा करने में जो समस्या आई थी, उसका निराकरण किया गया। समस्त वाहन मालिकों एवं ट्रक यूनियन के पदाधिकारी को माह फरवरी-2026 मै संचालित सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई, कार्यक्रम के दौरान अभिनव चौधरी माल /यात्री कर अधिकारी, ज्ञानेंद्र पाल वरिष्ठ सहायक, असीम रजा, प्रधान सहायक के साथ-साथ समस्त कार्यालय की कर्मचारी उपस्थित रहे।

गांव मंडवाल में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव मंडवाल में एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल सर्जन कैथल डॉ. रेणु चावला के निदेर्शानुसार तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें गांव के अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

■ भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती, टीबी, उच्च रक्तचाप व मधुमेह पर भी दी गई विस्तृत जानकारी

बैठक को संबोधित करते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मचारी श्रीमती अनिता ने कहा कि समाज में बेटियों की घटती संख्या चिंता का विषय है। यदि बेटियों की संख्या कम होगी तो सामाजिक असंतुलन व अपराध बढ़ेंगे। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से भ्रूण लिंग जांच न करवाने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि लिंग जांच की सूचना स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा सूचना सही पाए जाने पर सरकार द्वारा एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर जांच करवाने और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने की भी सलाह दी।

पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता पंकज ने टीबी के लक्षणों-दो सप्ताह से अधिक खांसी, बलगम में खून, लगातार बुखार, वजन घटना व रात में पसीना-की जानकारी देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा टीबी का उपचार निःशुल्क उपलब्ध है तथा निक्षय पोषण योजना के तहत मरीज को प्रतिमाह एक हजार रुपये पोषण सहायता दी जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मोईन खान ने उच्च रक्तचाप और मधुमेह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण स्तर पर इन बीमारियों की जांच व दवा उपलब्ध है। नियमित दवा सेवन से इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। बैठक में आशा वर्कर नीलम, सुनीता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

मीडिया समाज को जागरूक करता है : डॉ. हिमांशु छाबड़ा

विद्यार्थियों को मीडिया की जानकारी देते डॉ. हिमांशु छाबड़ा। (छायाः एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। यह बात मीडिया विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु छाबड़ा ने शहर के करनाल रोड़ पर मौजूद बाबा फतेह सिंह जी राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट के एक दिवसीय कैम्प और प्लेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सोशल मीडिया और रोजगार उप-विषय पर आयोजित विस्तार व्याख्यान के दौरान कही।

महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. नीलम तुरान ने डॉ. छाबड़ा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं डॉ. हिमांशु ने छात्रों से मीडिया के विभिन्न आयामों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नया मीडिया, संचार और उसके प्रकार, प्रक्रिया, मॉडल, लोक संपर्क, विज्ञापन तथा समाचार लेखन कला में पत्रकार की भूमिका, पत्रकारिता में रोजगार के अवसरों के बारे में छात्रों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण पूरा विश्व एक गाँव बन गया है। सोशल मीडिया की ज्यादातर साइट्स अमेरिका डील कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 80 प्रतिशत लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी को सोशल मीडिया का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए।

इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से कई मीडिया संबंधी सवाल पूछे जिसके विद्यार्थियों ने स्टीक उत्तर दिये क उन्होंने छात्रों से कहा कि मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर है। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज प्रबंधन का उनके व्याख्यान के लिए धन्यवाद किया और भविष्य में भी अपनी सेवाएं देने का वादा भी किया।

इस अवसर पर प्रो अनिल, प्रो. मीना, डॉ. हिना, डॉ. जगमोहन सिंह आदि समेत समस्त स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे।

सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए डीएमसी की अगुवाई में पुलिस की संयुक्त टीम रिपोर्ट दें: एडीसी डॉ. सुशील कुमार

वन विभाग के अधिकारी पूरे जिले में सड़कों के किनारे बढ़ी हुई झाड़ियों को हटवाने के लिए करें गंभीरता से कार्य

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि कैथल शहर में जरूरत अनुसार अपराध एवं सड़क हादसे रोकने के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों को लेकर डीएमसी की अगुवाई में पुलिस की संयुक्त टीम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद कैथल संबंधित प्वाइंटस पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, ताकि सड़क हादसों को रोकने सहित आपराधिक घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। पुलिस इन कैमरों की मदद से ऑनलाइन चालान जैसी कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कर पाएगी।

इसके अलावा वन विभाग के अधिकारी जिले भर की सड़कों के किनारे उग आई झाड़ियों की कटाई-छंटाई सुनिश्चित करें। ताकि वे हादसों का कारण न बनें।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण के कार्य को तय सीमा में पूरा करवाएं। कई बार अधूरे कार्य हादसों का का कारण बनते हैं। इसके अलावा चौक-चौराहों पर खराब पड़ी रेड लाइट की रिपोर्ट तैयार करते हुए शहरी निकाय अधिकारी इन्हें ठीक करवाएं।

एडीसी डॉ. सुशील कुमार शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में एजेंडे में शामिल सभी बिंदुओं पर एक-एक करके चर्चा की तथा अधिकारियों से पूर्ण फीडबैक ली। एडीसी ने कहा कि जिला में दुर्घटनाओं को रोकना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और इन सभी कार्यों को सामाजिक तौर पर प्राथमिकता से करें। कार्यों में कहीं भी लापरवाही न बरतें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी चौकों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखें, कहीं भी जाम जैसी स्थिति पैदा न होने दें। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मचारी अलर्ट होकर कार्य करें। बिना हेल्मेट व सीट बैलेट के लिए आमजन को जागरूक करें और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करते हुए चालानिंग की जाए। उन्होंने आरटीए को निर्देश दिए कि वे स्कूल बसों की चैकिंग को निरंतर जारी रखें।

एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के दुरुस्तीकरण कार्य में गति लाएं। विभाग से संबंधित जो-जो बिंदू एजेंडें में शामिल है, उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। एडीसी ने कैथल-चीका रोड, कैथल-करनाल रोड, ब्राह्मणीवाला, तितरम मोड से कैथल, राजौंद में निमार्णाधीन सड़क, गांव कौल की सडक, पूंडरी-काकौत रोड, खनौरी बाईपास रोड, पूंडरी-पाई रोड, नजदीक शहीद उधम सिंह पार्क रोड, नजदीक सिग्नस अस्पताल अंबाला रोड आदि स्थानों पर सड़कों पर हुए गड्ढों व सड़कों के नवनिर्माण को लेकर चल रही कार्रवाई की रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि यदि इन स्थानों पर कहीं काम चल रहा है तो वहां पर कार्य में गति लाएं। उन्होंने नेशनल हाईवे पर अवैध कटों को बंद करने, स्पीड लिमिट बोर्ड व अन्य साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत जारी निदेर्शों का भी गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही एजेंडे में शामिल सभी बिंदूओं पर संबंधित विभागों को काम पूरा करके एटीआर आरटीए कार्यालय में देने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हादसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि किसी हादसे में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उस परिवार की क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी को हादसों को रोकने के लिए एक टीम की तरह मिलकर काम करना चाहिए।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, आरटीए गिरिश कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह, डीएसपी सुशील प्रकाश, जीएम रोडवेज कमलजीत चहल, सीएमओ रेणू चावला, डीईओ सुभाष, डीआईपीआरओ नसीब सिंह सैनी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत स्ट्रॉलेज बनाने का विधि प्रदर्शन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। आईसीएआर-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) के निदेशक डॉ. धीर सिंह के मार्गदर्शन में डेरी विस्तार प्रभाग द्वारा संचालित फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत गांव कमालपुर रोडान और नगला रोडान में स्ट्रॉलेज बनाने का विधि प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 50 किसानों ने भाग लिया।

परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. गोपाल सांखला ने बताया कि फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन समय की मांग है। धान के भूसे सहित कृषि-औद्योगिक अपशिष्टों से पौष्टिक पशु आहार तैयार कर किसानों की लागत घटाई जा सकती है। प्रधान वैज्ञानिक (पशु पोषण) डॉ. नितिन त्यागी ने जानकारी दी कि डिस्टिलरी अपशिष्ट, मटर का छिलका या आलू चिप्स उद्योग के अपशिष्ट और धान के भूसे को 35:40:25 के अनुपात में मिलाकर साइलो पद्धति से 40 दिनों तक वायुरहित अवस्था में संरक्षित किया जाता है। तैयार स्ट्रॉलेज में लगभग 10-12% प्रोटीन और 58-60% कुल पाच्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसे खनिज मिश्रण के साथ संतुलित आहार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस अवसर पर किसानों को साइलेंज बैग वितरित किए गए। साथ ही 6 से 8 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय डेरी मेला-2026 में भाग लेने का आह्वान किया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और सतत डेरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' ने महीप कपूर को दी नई पहचान

नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' ने अभिनेता संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर को ऐसी पहचान दी, जो केवल संजय कपूर की पत्नी या सोनम कपूर की चाची तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 1982 में जन्मी और ऑस्ट्रेलिया में पली-बढ़ी महीप ने बॉलीवुड में कदम एक अभिनेत्री के तौर पर रखा था। महिप कपूर का बेबाक, नो-फिल्टर अंदाज और परिवार के प्रति समर्पण ने उन्हें दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने 1994 में फिल्म 'निगम' में काम किया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। अभिनय से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने करियर को नया मोड़ देते हुए ज्वेलरी डिजाइनिंग में कदम रखा और 'सत्यानी फाइन ज्वेल्स' के लिए ऐसे डिजाइन तैयार किए, जिन्हें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने अपनाया। महीप और संजय कपूर की शादी 1997 में हुई थी। बाहर से उनका रिश्ता एक खुशहाल फैमिली की तस्वीर जैसा दिखता था, लेकिन असलियत इससे अलग थी। 'बॉलीवुड वाइव्स' के दूसरे सीजन में महीप ने अपनी निजी जिंदगी का वह दर्दनाक सच साझा किया, जिससे दर्शक अनजान थे। उन्होंने बताया कि शादी के शुरुआती सालों में संजय कपूर ने उन्हें धोखा दिया था। जब उनकी बेटी शनाया कपूर छोटी थीं, तब संजय का किसी और महिला से संबंध था। इस खुलासे ने फैंस को हैरान कर दिया। महीप ने यह भी बताया कि अफेयर की जानकारी मिलते ही वह बेटी को लेकर घर से निकल गई थीं, हालांकि बाद में उन्होंने संजय को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फैसला अपने बच्चों शनाया और जहान के लिए लिया और अपनी शादी को एक और मौका देने का निर्णय सही साबित हुआ, क्योंकि आज दोनों एक मजबूत रिश्ता साझा कर रहे हैं। महीप कपूर को लोग अक्सर 'मामा बियर' कहकर पुकारते हैं। वह अपनी बेटी शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव रही हैं। सोशल मीडिया पर भी वह अपने बच्चों के साथ बिताए गए पलों को साझा करती रहती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि परिवार उनकी प्राथमिकता है। शनाया अब फिल्मों में कदम रख चुकी हैं, और महीप का समर्थन हर कदम पर उनके साथ दिखता है। ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में सफलता हासिल करने के बाद महीप आज एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर और रियलिटी शो स्टार के रूप में भी लोकप्रिय हैं।

एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्हें डराती है: अभिषेक बच्चन

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का कहना है कि एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्हें डराती है और एक्टर्स के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अभिषेक बच्चन ने एआई को लेकर अपनी राय साझा करते हुए कहा कि वह इस तकनीक के साथ बहुत कम्फर्टेबल नहीं हैं। उनके मुताबिक, एआई भविष्य में क्रिएटिव फील्ड में बड़े बदलाव ला सकता है और अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो इससे एक्टर्स के अवसरों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के सहारे एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स और तकनीकी प्रक्रियाएँ आसान हो जाएंगी, जिससे फिल्म निर्माण का समय और बजट दोनों कम होंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक्टिंग जैसे मानवीय कला के क्षेत्र में एआई कभी भी उस 'जान' को नहीं ला सकता, जो किसी कलाकार की आत्मा से निकलकर पर्दे पर दिखाई देती है। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने कई एआई से तैयार चीज़ें देखी हैं जो देखने में बेहद आकर्षक और परफेक्ट लगती हैं, लेकिन उनमें मानवीय भावनाओं की गर्माहट और असलियत नहीं होती। उनका मानना है कि कलाकार की आत्मा, उसकी कमियाँ और उसकी अनूठी अभिव्यक्ति ही उसे खास बनाती हैं, और यही बात एआई कभी हासिल नहीं कर सकता।

वेब सीरीज हसरतें सीजन 3 को लेकर सुर्खियों में शिवांगी वर्मा

बॉलीवुड अभिनेत्री शिवांगी वर्मा इन दिनों वेब सीरीज हसरतें सीजन 3 को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें अभिनेत्री के एपिसोड का टाइटल 'मिडनाइट ब्राइड' है, जिसमें उन्होंने एक विधवा का किरदार निभाया है। बातचीत में शिवांगी ने बताया कि 'हसरतें' पहले से ही बेहद लोकप्रिय सीरीज है और वे इसकी फैन रही हैं। ऐसे में जब उन्हें 'सीजन 3' का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने कहा, 'मैं मेकर्स की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सीरीज के लिए चुना और मुझ पर भरोसा दिखाया। यह प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है।' अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में बताया कि यह उनके असली व्यक्तित्व से बिल्कुल उलट है। असल जीवन में वे काफी मॉडर्न, फैशनेबल और स्टाइलिश हैं, जबकि शो में वे एक ऐसी विधवा बनी हैं जिन्हें समाज की रूढ़िवादी अपेक्षाओं के साथ दिखाया गया है। उन्होंने कहा, 'समाज में अक्सर विधवा महिलाओं पर मेकअप न करने, रंगीन कपड़े न पहनने और साधारण रहने जैसे कई दबाव डाल दिए जाते हैं। इस किरदार को निभाते हुए मुझे एहसास हुआ कि सादगी में भी अलग तरह की खूबसूरती होती है।' शिवांगी बताती हैं कि शूटिंग के दौरान उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किरदार की भावनाओं और उसकी परिस्थितियों को सही तरह से दर्शाया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद इस रोल ने उन्हें काफी कुछ सिखाया। शो के प्रसारण के बाद उन्हें हर तरफ से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसे वे अपने करियर का बड़ा सम्मान मानती हैं। अपने काम के प्रति गंभीर रहने वाली शिवांगी कहती हैं कि उनके लिए कहानी सबसे अधिक मायने रखती है। यदि स्क्रिप्ट भावनाओं से जुड़ी हो और उन्हें बतौर अभिनेत्री चमकने का मौका दे, तो वे पूरी समर्पण के साथ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं। उन्होंने कहा, 'अच्छी कहानी हो तो मैं बाकी चीजों को भूल जाती हूं। मैं खासकर महिला-केंद्रित किरदारों की ओर आकर्षित होती हूं, क्योंकि ऐसे रोल में भावनाओं और अभिव्यक्ति के कई आयाम होते हैं।' भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए शिवांगी ने बताया कि उन्हें रोमांटिक थ्रिलर करने की काफी इच्छा है। इसके अलावा यदि कोई दमदार बायोपिक का प्रस्ताव मिलता है, तो वह भी वे जरूर करना चाहेंगी।

कला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं : श्वेता त्रिपाठी

कला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त जरिया भी है। यह कहना है अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी का। इसी सोच के साथ उन्होंने हाल ही में अपनी पहली क्वीर फिल्म मुझे जान ना कहो मेरी जान को प्रोड्यूस करने की घोषणा की है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम और यह एक संवेदनशील क्वीर प्रेम कहानी है, जिसके इस साल फ्लोर पर आने की उम्मीद है। फिल्म में श्वेता स्वयं भी अभिनय कर रही हैं। प्रोडक्शन की दुनिया में यह श्वेता का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले वे क्वीर विषय पर आधारित थिएटर प्ले कॉक को भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जो ब्रिटिश लेखक माइक बार्टलेट के ओलिवर अवॉर्ड जीत चुके ड्रामा पर आधारित है। यह नाटक देश के कई शहरों में प्रदर्शित हुआ था और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। श्वेता कहती हैं कि यह उनके लिए सिर्फ एक पेशेवर निर्णय नहीं, बल्कि निजी स्तर पर भी जुड़ा हुआ कदम है। उन्होंने कहा, 'अगर समाज में बदलाव चाहिए, तो पहल खुद से करनी होती है। महिलाओं और क्वीर समुदाय की कहानियां हमेशा रही हैं, लेकिन उन्हें वह स्थान और सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं। अब जब मुझे चुनने और बनाने का मौका मिला है, तो मैं इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहती हूं।' श्वेता का मानना है कि क्वीर कहानियों को असरदार बनाने के लिए उन्हें सनसनीखेज होने की जरूरत नहीं होती। कई बार ये कहानियां बेहद सरल, कोमल और दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं, जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक जगह बनाए रखती हैं। श्वेता आगे कहती हैं कि उन्हें वह रास्ता अब साफ दिखाई देता है, जिस पर वे आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाओं की कहानियों को मंच देना, क्वीर आवाज़ों को बढ़ावा देना और अपने फैसलों में ईमानदारी बनाए रखना। उनके अनुसार यही उनके लिए एक कलाकार के रूप में अपनापन और उद्देश्य दोनों का भाव पैदा करता है। अभिनेत्री जल्द ही दर्शकों के सामने एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ होने वाली हैं। वे मिर्जापुर-द मूवी में नजर आएंगी, जो 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु और रसिका दुग्गल सहित कई पुराने और नए कलाकार दिखाई देंगे। बता दें कि अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी अब सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि महिलाओं और क्वीर समुदाय की कहानियों को मुख्यधारा में मजबूत जगह दिलाने के लिए प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रही हैं।

इमेज को लेकर सजग थी, इसीलिए ठुकराए कई ऑफर: रवीना टंडन

90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन अपने ग्लैमरस अंदाज़ से लेकर निजी जीवन तक सुर्खियों में रही हैं। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के ऐसे फैसलों पर बात की है, जो आज भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। रवीना ने खुलासा किया कि उन्होंने निर्माता-निर्देशक करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है और सुपरस्टार शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने छैंया छैंया को करने से इनकार कर दिया था और इसके पीछे की वजहें दिलचस्प हैं। रवीना ने बताया कि 90 के दशक में उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट ऑफर होते थे, लेकिन वह अपनी इमेज को लेकर बेहद सजग थीं। फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना का रोल, जिसे बाद में अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने निभाया, पहले रवीना को ऑफर हुआ था। लेकिन रवीना ने यह रोल ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने दौर की दूसरी बड़ी स्टार काजोल के अपोजिट सेकंड लीड निभाना नहीं चाहती थीं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने करण जौहर से साफ कहा 'काजोल मेरी ही जनरेशन की हैं, मैं उनके पीछे खड़ी नहीं हो सकती।' रवीना ने हंसते हुए कहा कि करण जौहर आज भी मजाक में इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्होंने उनकी पहली फिल्म ठुकरा दी थी। हालांकि यह रोल रानी मुखर्जी के करियर का टर्निंग प्वाइंट बन गया और फिल्म आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इसके अलावा, रवीना ने फिल्म दिल से के मशहूर गाने छैंया छैंया, जिसमें बाद में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा दिखीं, को भी करने से मना कर दिया था। उन्हें डर था कि 'शहर की लड़की' जैसे सुपरहिट गाने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में 'आइटम सॉन्ग गर्ल' का टैग न दे दिया जाए। उस दौर में एक्ट्रेसेस के लिए स्टीरियोटाइप होना आसान था, इसलिए उन्होंने गाना छोड़ दिया। रवीना का कहना है कि उन्हें अपने निर्णयों पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि हर अभिनेता अपने करियर को अपनी समझ से दिशा देता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन अवसरों को उन्होंने छोड़ा, वे रानी मुखर्जी और मलाइका अरोड़ा के लिए माइलस्टोन साबित हुए।

फिल्म 'मैं हूं ना' को लेकर फराह ने किया बड़ा खुलासा

अपनी सुपरहिट फिल्म 'मैं हूं ना' को लेकर बॉलीवुड फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट निभाया गया चांदनी का आइकॉनिक रोल शुरुआत में सुष्मिता सेन को नहीं, बल्कि अभिनेत्री समीरा रेडडी को ऑफर किया जाना था। फराह ने यह राज अपने यूट्यूब व्लॉग में समीरा रेड्डी के साथ हुई हालिया बातचीत के दौरान खोला। फराह ने बताया कि उन्होंने समीरा को पहली बार 'आहिस्ता कीजिए बातें' म्यूजिक वीडियो में देखा था, जहां इंडियन ट्रेडिशनल लुक में उनकी खूबसूरती ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। उस समय फराह को लगा कि 'मैं हूं ना' में चांदनी का रोल समीरा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह सुनकर समीरा भी हैरान रह गईं और मजाकिया अंदाज में पूछा कि फिर उन्हें कास्ट क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में फराह ने बताया कि समीरा के करियर की दिशा उस समय बदल चुकी थी, क्योंकि वह सोहेल खान के साथ अपनी डेब्यू फिल्म 'मैने दिल तुझको दिया' कर चुकी थीं। इस फिल्म के कारण उनकी स्क्रीन इमेज और प्रोजेक्ट्स अलग दिशा में जा रहे थे, जिसके चलते 'मैं हूं ना' के लिए सुष्मिता सेन को चुनना पड़ा। फराह ने साफ कहा कि समीरा उनकी पहली पसंद थीं, लेकिन उस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। समीरा रेड्डी ने इस खुलासे पर खुशी तो जताई, लेकिन थोड़ी निराश भी दिखीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है क्योंकि 'मैं हूं ना' उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने सुष्मिता सेन की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म में सुष्मिता द्वारा निभाया गया चांदनी का ग्लैमरस साड़ी लुक आज भी दर्शकों के बीच बेहद मशहूर है। फिल्म रिलीज़ के बाद यह फराह खान के निर्देशन करियर की धमाकेदार शुरुआत साबित हुई। दूसरी ओर, समीरा रेड्डी 'डरना मना है', 'मुसाफिर', 'नो एंट्री' और 'रेस' जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन बाद में उन्होंने मेनस्ट्रीम सिनेमा से दूरी बना ली।

बदले हुए लुक को लेकर सुर्खियों में राजकुमार राव

हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव एक शॉर्ट फिल्म के इवेंट में नजर आए, जहां रेड कार्पेट पर उनका अंदाज देखकर पैपराज़ी भी दंग रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही राजकुमार राव की ताजा तस्वीरों और वीडियो में बदले हुए लुक में नजर आ रहे है। राजकुमार राव का वजन बढ़ा हुआ दिखता है, हेयरलाइन बदली हुई नजर आ रही है और उनकी पूरी पर्सनैलिटी में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। उनके इस नए लुक ने फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं, लेकिन धीरे-धीरे असली वजह सामने आ गई है। एक्टर के करीबी सूत्र ने बताया कि राजकुमार राव पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके लुक में आया यह बदलाव जानबूझकर किया गया है। सूत्र के अनुसार, वे अपनी अगली बायोपिक 'निकम' के लिए यह भारी-भरकम रूप लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म के किरदार के लिए उन्होंने काफी वजन बढ़ाया है क्योंकि वे अपनी उम्र से काफी बड़े एक जाने-माने व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और राजकुमार राव इस समय दोबारा वजन कम करने की प्रक्रिया में हैं। जानकारी के अनुसार, यह बायोपिक भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में गांगुली की क्रिकेट यात्रा, शुरुआती संघर्ष, कप्तान के रूप में उनके फैसले और भारतीय क्रिकेट के बदलाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया जाएगा।

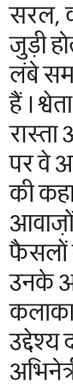

'बैटल ऑफ गलवान' ने असली सैनिकों की सीरीज की जारी

'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म के मेकर्स ने असली आर्मी वेटरन्स और उनके परिवारों की कहानियों से जुड़ी एक विशेष वीडियो सीरीज जारी की है, जो उन खामोश ताकतों को सम्मान देती है, जो हर सैनिक के पीछे चुपचाप खड़ी रहती हैं। इन वीडियो को साझा करते हुए मेकर्स ने लिखा कि 'बैटल ऑफगलवान' उन परिवारों को सलाम करता है जिन्होंने हर पोस्टिंग, हर विदाई और हर वापसी को अपने दिल से जिया है। पहले वीडियो में तीसरी गोरखा राइफल्स के कर्नल महीप सिंह चड्ढा की बेटी मिसेज गानवी चड्ढा नज़र आती हैं। कर्नल चड्ढा 1965 और 1971 की जंग में शामिल रहे थे। मिसेज चड्ढा याद करती हैं कि कैसे उनके पति फील्ड एरिया में तैनात रहते थे और उनसे बात करने के लिए लोकल एक्सचेंज के जरिए कॉल बुक करनी पड़ती थी, जिसमें पूरा प्रोटोकॉल निभाना होता था।
वह बताती हैं कि परिवार उन्हें कितना याद करता था, खासकर उनका पसंदीदा खाना बनाते समय। जब वह छुट्टी लेकर घर लौटते थे, तो वही खाना साथ बैठकर खाने में एक अलग ही खुशी होती थी। दूसरे वीडियो में 16 बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीप मनचंदा (रिटायर्ड) की पत्नी मिसेज सविंदर मनचंदा उन तनाव भरी यादों को साझा करती हैं, जब उनके पति की यूनिट को अरुणाचल प्रदेश के वांगचुक जनजाति वाले क्षेत्र में भेजा गया था। वह बताती हैं कि उस इलाके में लगातार खतरा बना रहता था। टेलीफोन लाइनें बहुत दूर थीं और आवाज भी साफ नहीं आती थी, लेकिन किसी भी तरह पति की आवाज सुन लेना उनके लिए बड़ा सुकून था। तीसरे वीडियो में खुद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीप मनचंदा दिखाई देते हैं, जिन्होंने 1972 से 2003 तक देश की सेवा की। वह अपने 32 साल के आर्मी सफर को जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बताते हैं। गलवान घाटी के संघर्ष समेत कई कठिन ऑपरेशन्स को याद करते हुए उन्होंने भारतीय सेना और अपने साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इन भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से सलमान खान फिल्म्स न सिर्फसैनिकों की बहादुरी को सम्मान दे रहा है, बल्कि उन परिवारों की कुर्बानियों को भी सलाम कर रहा है, जो हर वर्दी के पीछे की असल ताकत होते हैं। सलमा खान के प्रोडक्शन और अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी 'बैटल ऑफ गलवान' बहादुरी, बलिदान और मानवीय रिश्तों की गहराई को दर्शाने की कोशिश करती है। चित्रांगदा सिंह भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाती है। बता दें कि 'बैटल ऑफगलवान' के टीज़र को मिली दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया के बाद सलमान खान फिल्म्स लगातार देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर रहा है। हाल ही में रिलीज़ हुए इसके गाने 'मातृभूमि' और 'मैं हूँ' ने लोगों के दिलों में जोश और भावनाओं का एक नया उभार पैदा किया है।